

## Title: Regarding summit level talks between India and Pakistan.

**MR. SPEAKER:** Now, the hon. Prime Minister will make the statement which will be telecast live.

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था।

उनकी यात्रा से पहले मैंने भारत-पाकिस्तान संबंधों की भावी संभावनाओं के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया था। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से हमारे इस विचार का समर्थन किया था कि इस यात्रा को पाकिस्तान के साथ स्थाई शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए अवसर तलाशने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शिमला समझौता तथा लाहौर घोषणा के आधार पर हम चाहते थे कि निमंत्रण तथा तत्पश्चात् यात्रा के माध्यम से बातचीत के व्यापक ढांचे को सुदृढ़ किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया द्विपक्षीय मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सके। हमने सीमा-पार से जारी आतंकवाद को भी बातचीत के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रखा था।

यात्रा से पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण और विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की थी जो शांति और सुरक्षा, परमाणु और गैर-परमाणु हथियारों के बारे में विश्वास पैदा करने के उपायों, दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क, जनहित से जुड़े मुद्दे, शिक्षा, युवाओं का एक दूसरे के देश में आना-जाना तथा व्यापार से संबंधित थे। हमारा विश्वास है कि भारत तथा पाकिस्तान के लोगों द्वारा इन निर्णयों का व्यापक स्वागत किया गया है। सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ, बेगम मुशर्रफ के साथ 14 जुलाई को नई दिल्ली आए थे। उन्हें समारोहपूर्वक पूरा सम्मान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने उन्हें राजकीय भोज दिया। उप-राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने उनसे मुलाकात की। मैंने उनके सम्मान में दोपहर का भोज दिया। दिनांक 15 और 16 जुलाई को आगरा में प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुशर्रफ और मैंने 5 घंटे से भी अधिक समय तक आमने-सामने बैठकर व्यापक चर्चा की। हमने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत की।

इन चर्चाओं के दौरान मैंने जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दों पर प्रगति के लिए विश्वास का माहौल पैदा करने के महत्व पर बल दिया। मैंने अन्य विशिष्ट मुद्दे भी उठाए जो शांति की प्रक्रिया में सहायक हो सकते थे। इनमें पाकिस्तान की जेलों में कैद 54 भारतीय युद्धबंदियों का मुद्दा, कुख्यात आतंकवादियों और अपराधियों, जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है, का प्रत्यर्पण करने, पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिन्दू मंदिरों की देखरेख करने, पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा परस्पर लाभ वाले व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे शामिल थे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में यह बात बता दी कि भारत के पास आतंकवाद और हिंसा को पूरी तरह से कुचल देने के लिए दृढ़ संकल्प, शक्ति और क्षमता है। मैं इसी दृढ़ संकल्प को आज इस सदन में दोहराना चाहता हूँ।

अपनी बात में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने केवल जम्मू और कश्मीर पर ही चर्चा की। माननीय सदस्य उनके सभी विचारों से अवगत होंगे, क्योंकि इनका हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था।

हमारे विचारों में स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद, हम संयुक्त दस्तावेज के मसौदे में इस मतभेद को कम करने की दिशा में आगे बढ़े। हम दस्तावेज में अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर और शिखर स्तर पर बैठकों के आयोजन सहित सभी मुद्दों पर भावी वार्ता प्रक्रिया की रूपरेखा को शामिल करना चाहते थे। हमने परमाणु और परम्परागत हथियारों के प्रति विश्वास का माहौल बनाने के उपायों सहित शांति तथा सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर, आतंकवाद के मुद्दों और संयुक्त बातचीत से उभर कर सामने आये अन्य सभी मुद्दों के समाधान के प्रस्ताव रखे। किन्तु अंत में हमें संयुक्त दस्तावेज के अपने प्रयासों को छोड़ना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के 'समाधान' पर अड़ा रहा। पाकिस्तान सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को स्वीकार करने और उसका हल निकालने का भी इच्छुक नहीं था। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और मैं इस बात पर सहमत थे कि हम संयुक्त दस्तावेज जारी करने के लिए अपने बुनियादी सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जम्मू और कश्मीर के समाधान के बारे में गहरे मतभेद हैं किन्तु, हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना सम्बन्धों में चहुँमुखी प्रगति का जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में हमारी बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस वाद-विवाद से कि जम्मू और कश्मीर एक "मुख्य मुद्दा" है या नहीं, कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम इस राज्य में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद और हिंसा की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जम्मू और कश्मीर में भाड़े के विदेशी आतंकवादियों द्वारा और विदेशी धन से जो हिंसक गतिविधियां जारी हैं वे और कुछ नहीं सिर्फ आतंकवाद है। निर्दोष स्त्री, पुरुष और बच्चों की हर रोज हो रही हत्या को हम न 'जेहाद' कह सकते हैं और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन। यह विचारणीय है कि आगरा शिखर वार्ता के समाप्त होते ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर जा रहे हमारे तीर्थयात्रियों को मार दिया गया। और अभी दो दिन पहले एक और नरसंहार हुआ जिसमें एक ही समुदाय के लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए। इसीलिए, सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को खत्म करने से पाकिस्तान का इनकार ही परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है।

पाकिस्तान "कश्मीरी लोगों" की इच्छा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान चाहता है। मुझे विश्वास है कि हरेक कश्मीरी चाहे वह कश्मीर घाटी का हो, या जम्मू, लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उत्तरीक्षेत्र या शाक्सगाम घाटी का, उसकी सबसे पहली इच्छा अमन-चैन, सुरक्षा और आजादी के साथ रहने की है ताकि वह आर्थिक प्रगति कर सके।

हमारी यह लगातार कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें उनका यह मौलिक अधिकार दें। अधिकांश कश्मीरियों के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी जायज मांगों को सामने लाते हैं। हम कश्मीर की सभी अन्य विचारधाराओं को सुनने को तैयार हैं, चाहे वे कितने ही छोटे तबके का प्रतिनिधित्व क्यों न करते हों, बशर्त कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इसी भावना के साथ हमने ऑल पार्टी हुरियत कान्फरेंस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की पेशकश की थी।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मुझे पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी हमारे विदेश मंत्री को आमंत्रित किया है। इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार, पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध जारी रहेंगे। हम बातचीत और परस्पर मेल मिलाप को जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान को यह समझाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमारा द्विपक्षीय सहयोग केवल किसी एक मुद्दे के समाधान की खातिर रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम आगरा में संयुक्त दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सके, फिर भी हम आपसी समझ पैदा करने में कुछ हद तक सफल हुए। इसी आधार पर ही हम समझौतों के दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेंगे। निस्संदेह, सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की चिंता को भावी बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दस्तावेज में शामिल किया जाना होगा।

में यह भी कहना चाहूंगा कि हम किसी प्रचार या बहस के किसी मुद्दे की तलाश में नहीं हैं। हम संयम और गम्भीरता से कूटनीति जारी रखेंगे। शान्ति, मित्रता और सहयोगपूर्ण सम्बन्धों के लिए हमारे प्रयास प्रबलता से जारी रहेंगे।

-----

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का पाकिस्तान पर हमला करना एक ही इलाज हो सकता है।<sup>12</sup> ( ब्यवधान )

**अध्यक्ष महोदय** : इस सबजैक्ट को शाम को डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं?

...( ब्यवधान )

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

( *Interruptions* ) \*

MR. SPEAKER: We are discussing this matter today evening.

...( *Interruptions* )

MR. SPEAKER: We are discussing this matter at 4.00 p.m.

...( *Interruptions* )

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

( *Interruptions* ) \*

\* Not Recorded